



भारत-ब्राजील में क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर समझौता हुआ

5 साल में 20 अरब डॉलर व्यापार का लक्ष्य : पीएम मोदी

नई दिल्ली,21 फरवरी 2026। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत और ब्राजील आने वाले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन डॉलर से आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार केवल आंकड़ों का विषय नहीं बल्कि पारस्परिक विश्वास और मजबूत रणनीतिक साझेदारी का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को हैदराबाद हाउस में ब्राजील के राष्ट्रपति लुई इनासियो लुला दा सिल्वा के साथ संयुक्त पत्रकार वार्ता के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत-ब्राजील संबंधों को राष्ट्रपति लुला की दूरदृष्टि और प्रेरक नेतृत्व का लंबे समय से लाभ मिलता रहा है।

बीते वर्षों में कई अवसरों पर हुई मुलाकातों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भेंट में उन्होंने भारत के प्रति राष्ट्रपति लुला की गहरी मित्रता और विश्वास को महसूस किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति लुला ने ऐतिहासिक एआई इंपैक्ट समिट में भाग लेकर दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को नई ऊर्जा प्रदान की है। उन्होंने राष्ट्रपति के साथ आए बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि यह दल दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक विश्वास का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्राजील लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत-कोसोसुर व्यापार समझौते के विस्तार से आर्थिक सहयोग और सुदृढ़ होगा।

मोदी बोले...भारत-ब्राजील एनर्जी के क्षेत्र में काम कर रहे...

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा...कि ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग भारत और ब्राजील के रिश्तों की मजबूत नींव है। तेल और गैस के अलावा अब दोनों देश रिन्यूएबल एनर्जी,इथेनॉल मिक्सचर और टिकाऊ विमानन ईंधन जैसे नए क्षेत्रों में भी तेजी से साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्लोबल बायोफ्यूल गठबंधन में ब्राजील की सक्रिय भागीदारी यह दिखाती है कि दोनों देश सुरक्षित भविष्य के लिए एक साथ प्रतिबद्ध हैं। मोदी ने बताया कि ब्राजील ने भारत को आपदा प्रतिरोधी इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन की सह-अध्यक्षता का प्रस्ताव भी दिया है। उन्होंने इस पहल के लिए राष्ट्रपति लुला को बधाई दी और कहा कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ब्राजील का लंबा अनुभव इस गठबंधन को और मजबूत बनाएगा।

क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर समझौता

भारत और ब्राजील के बीच क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह समझौता मजबूत संपाई चैन बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि रक्षा क्षेत्र में भी भारत और ब्राजील के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। यह दोनों देशों के बीच आपसी भरोसे और रणनीतिक समझ का अच्छा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि आगे भी इस फायदे वाली साझेदारी को और मजबूत किया जाएगा। मोदी ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य और दवा क्षेत्र में सहयोग की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। भारत ब्राजील को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता की दवाओं की आपूर्ति बढ़ाने के लिए काम करेगा।

ब्राजीली राष्ट्रपति बोले...भारत में छठी बार आकर खुशी हो रही...

ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा ने कहा, 'मेरे प्रिय मित्र मोदी, इस देश में छठी बार आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। भारत और ब्राजील की यह मुलाकात बेहद खास है। हम सिर्फ ग्लोबल साउथ की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकतें ही नहीं हैं,बल्कि यह एक डिजिटल शक्ति और एक नवीकरणीय ऊर्जा शक्ति की मुलाकात है।' उन्होंने कहा कि भारत और ब्राजील दोनों ही विविधताओं से भरे बड़े देश हैं,सांस्कृतिक उद्योग के बड़े केंद्र हैं और हम दोनों शांति का समर्थन करते हैं।



लुला बोले...ब्राजील को भारत से बहुत उम्मीदें

ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा ने कहा...भारत को लेकर ब्राजील की उम्मीदें बहुत बड़ी हैं। अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे, तो भारत-ब्राजील के रिश्ते और मजबूत होंगे।' उन्होंने कहा कि दोनों देश मिलकर ग्लोबल साउथ को भी मजबूत करेंगे,ताकि दुनिया को दो बड़ी महाशक्तियों के बीच किसी नए शीत युद्ध जैसी स्थिति का सामना फिर कभी न करना पड़े।

एनर्जी कोऑपरेशन हमारे रिश्ते का एक मजबूत स्तंभ : पीएम मोदी

हैदराबाद हाउस में साक्षा प्रेस वार्ता में पीएम मोदी ने कहा ...एनर्जी कोऑपरेशन हमारे रिश्ते का एक मजबूत स्तंभ रहा है। हाइड्रोकार्बन के साथ हम रिन्यूएबल एनर्जी, इथेनॉल ब्लेंडिंग और सरटेनेबल एविएशन फ्यूल जैसे कई एरिया में भी कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में ब्राजील का एक्टिव पार्टिसिपेशन ग्रीन फ्यूलर के लिए हमारे साक्षा प्रतिबद्धता को दिखाता है। ब्राजील ने डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोएलिशन की को-चेयर करने का भी प्रस्ताव दिया है। मैं इस पहल के लिए राष्ट्रपति लुला को बधाई देता हूं। इस क्षेत्र में ब्राजील का बड़ा अनुभव सीबीआरआई को और मजबूत करने में काफी मदद करेगा।'

दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट...लाल किला और चांदनी चौक के आसपास सुरक्षा कड़ी



नई दिल्ली,21 फरवरी 2026। दिल्ली में एक बार फिर आतंकी हमले की आशंका को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। इस खुफिया जानकारी के बाद राजधानी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) दिल्ली में आईईडी हमले की साजिश रच रहा है। सूत्रों के अनुसार आतंकियों के निशाने पर ऐतिहासिक लाल किला स्थित मंदिर और उसके आसपास का इलाका हो सकता है। खासकर भीड़भाड़ वाले चांदनी चौक स्थित प्रमुख मंदिर को लेकर इनपुट मिला है। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी विशेष स्थल का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने सवेदनशील धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 6 फरवरी को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में स्थित टेरेलाई इमाम बाराह में जुमे की नमाज के दौरान हुए विस्फोट के बाद यह आतंकी संगठन भारत में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। उस हमले में कई लोगों की मौत हुई थी और कई अन्य घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को जैसे ही संभावित खतरे की जानकारी मिली, वेस ही लाल किला, चांदनी चौक और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बाजारों, पार्किंग स्थलों और धार्मिक स्थलों की सघन जांच की जा रही है।

असम में पहली बार सीआरपीएफ की स्थापना दिवस परेड,पूर्वोत्तर के लिए गौरव का क्षण : अमित शाह



गुवाहाटी,21 फरवरी 2026। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि असम में पहली बार आयोजित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 87वें स्थापना दिवस की परेड पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ के 86 वर्ष के इतिहास में पहली बार यह परेड पूर्वोत्तर में आयोजित की गई है। सरसोजाई स्थित अर्जुन भोगेश्वर बरुवा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने बताया कि वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया था कि सीआरपीएफ का स्थापना दिवस समारोह देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष यह आयोजन असम में हो रहा है। उन्होंने सीआरपीएफ के जवानों के योगदान और बलिदान को याद करते हुए कहा कि अब तक 2,270 जवान देश की सेवा में शहीद हुए हैं। इनमें लगभग 700 पूर्वोत्तर क्षेत्र में, 540 जम्मू-कश्मीर में और 79 असम में शहीद हुए। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर, झारखंड और पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्र कभी गंभीर रूप से प्रभावित माने जाते थे, लेकिन सुरक्षा बलों के सतत प्रयासों से वहां की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। गृह मंत्री ने बताया कि दो बटालियन से शुरू हुआ सीआरपीएफ आज 243 बटालियनों और 3.89 लाख से अधिक कर्मियों की शक्ति वाला बल बन चुका है। उन्होंने कहा कि उग्रवाद और वामपंथी उग्रवाद से निपटने में सीआरपीएफ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। इससे पहले 20 फरवरी को गृह मंत्री ने कछार जिले के काटीगड़ा स्थित नतुनपुर में भारत-बांग्लादेश सीमा पर 'वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम' के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 17 राज्यों के 334 ब्लॉकों और लगभग 1,954 गांवों का विकास किया जाएगा, जिनमें असम के 140 गांव शामिल हैं।

एआई समिट में हंगामे पर बवाल,बीजेपी का देशभर में उग्र प्रदर्शन..

मायावती-अखिलेश बोले...एआई समिट में कांग्रेस का प्रदर्शन गलत

नई दिल्ली,21 फरवरी 2026। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बजपा चीफ मायावती ने दिल्ली के भारत मंडपम में एआई समिट में शुक्रवार को कांग्रेस के प्रदर्शन को गलत बताया है। अखिलेश ने कहा...जब दुनियाभर से डेलीगेट्स आये हो तो ऐसा हंगामा नहीं करना चाहिए। सरकार से लड़ाई हमारा इंटर्नल मामला है,फरैन डेलीगेट्स के सामने हमारे देश का अपमान होता है। मायावती ने एक्स पर लिखा-कांग्रेस का प्रदर्शन निन्दनीय है। अगर यह सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का नहीं होता तो अलग बात थी, लेकिन एआई समिट के दौरान ऐसा व्यवहार करना चिन्ता की बात है। इधर,कांग्रेस केएआई समिट में हंगामा करने के विरोध में भाजपा ने दिल्ली, महाराष्ट्र,गुजरात,बिहार,तेलंगाना और जम्मू-कश्मीर में प्रदर्शन किया। मुंबई

के मुलुंड में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के काफिले को काले झंडे दिखाए। उधर,एआई समिट में हंगामा करने वाले कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं को आज पटियाला कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि प्रदर्शन करने वाले नेपाल के Gen-Z आंदोलन से प्रेरित थे। यह प्रदर्शन एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। हंगामे के दौरान कई ग्लोबल लीडर्स और टेक इंडस्ट्री के एक्सपर्ट वहां मौजूद थे। पुलिस ने कहा कि यह जांच करनी है कि आरोपियों ने पीएम मोदी की फोटो वाली टी-शर्ट किससे छपवाई। इसके अलावा उनके मोबाइल फोन भी बरामद करने हैं। इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि ने चारों आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया।

कांग्रेस मुख्यालय पर भाजपा का प्रदर्शन,कई कार्यकर्ता हिरासत में..

भारत मंडपम में चल रहे एआई शिखर सम्मेलन में भारतीय युवा कांग्रेस के प्रदर्शन के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर शनिवार को प्रदर्शन किया। भाजपा ने कांग्रेस के प्रदर्शन की निंदा करते हुए इसे देश की छवि खराब कराने की कोशिश बताया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया और कुछ देर बाद उन्हें छोड़ दिया। प्रदर्शन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा,पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद मनोज तिवारी,प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार भाटिया,विष्णु मितल,प्रवीण शंकर कपूर,उपमहापौर जयभगवान यादव,जिलाध्यक्ष वीरेन्द्र बबबर,माया विट और अन्य लोग मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों के बैरिकेड्स तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश के दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा और अन्य कार्यकर्ताओं को तुंगलकोरोड स्थित थाने ले गई, जहां से लगभग एक घंटे बाद उनको वेंतावली देकर छोड़ दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा ने कहा कि एआई शिखर सम्मेलन भाजपा का नहीं भारत राष्ट्र का कार्यक्रम था और उसमें घुस कर प्रदर्शन करना सीधा राष्ट्रद्रोह है।



कांग्रेस ने भारत के गौरव को किया बदनाम : मनोज तिवारी

इस विरोध प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा के साथ शामिल हुए सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए तिवारी ने कहा, 'एआई शिखर सम्मेलन में 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं,जो भारत की प्रति की सराहना कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने 'किराये के गुंडों' को भेजकर वैश्विक मंच पर भारत की छवि धूमिल करने का प्रयास किया है।' उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस का यह कुत्त देशद्रोह की श्रेणी में आता है और देश की जनता इस अपमान का जवाब जरूर देगी।

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश

प्रयागराज,21 फरवरी 2026।

इलाहाबाद जिला न्यायालय पॉक्सो एक्ट की अदालत ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य दंडी स्वामी प्रत्यक्त चैतन्य मुकुंदानंद गिरि के खिलाफ बच्चों के यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश शाकुंभरी पीठीधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए स्पेशल कोर्ट ने दिया है। स्पेशल कोर्ट पॉक्सो के न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने जगदुरु ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ बच्चों का यौन शोषण करने के आरोप में झूंसी थाने में



एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य दंडी स्वामी प्रत्यक्त चैतन्य मुकुंदानंद गिरि के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। न्यायालय ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और मामले की विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया। न्यायालय के आदेश के बाद अब झूंसी थाने में मामला दर्ज किया जाएगा।

भारत के विजन पर 88 देशों की मुहर...'सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय' पर वैश्विक सहमति

नई दिल्ली,21 फरवरी 2026।

भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026'को एक बड़ी कुटनीतिक और तकनीकी सफलता मिली है। 88 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने इस शिखर सम्मेलन के घोषणापत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को इसकी घोषणा करते हुए साफ किया कि दुनिया ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'मानव-केंद्रित एआई दृष्टिकोण' को खुले तौर पर स्वीकार कर लिया है। यह कदम वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के सुरक्षित, समान और जवाबदेह विकास की दिशा में एक अहम मील का पत्थर माना जा रहा है।



वैश्विक सहयोग और 'सर्वजन हिताय' का सिद्धांत : केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इस उन्नत तकनीक और इसके आर्थिक फायदों की पहुंच दुनिया भर में समाज के हर वर्ग तक सुनिश्चित हो सके।

खुशी) के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया है। इस विजन का मुख्य लक्ष्य एआई संसाधनों का इस तरह से लोकतंत्रीकरण करना है कि इस उन्नत तकनीक और इसके आर्थिक फायदों की पहुंच दुनिया भर में समाज के हर वर्ग तक सुनिश्चित हो सके।

शिखर सम्मेलन से जुड़ी प्रमुख नीतिगत बातें...

यह शिखर सम्मेलन 16 फरवरी से 20 फरवरी 2026 तक नई दिल्ली के 'भारत मंडपम' में आयोजित किया गया। इस आयोजन ने कई अहम मोर्चों पर वैश्विक नीतियां तय करने का मजबूत आधार रखा है- ग्लोबल साउथ का नेतृत्व: यह 'ग्लोबल साउथ' में आयोजित होने वाला दुनिया का पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन था। हितधारकों का महामंच: इस आयोजन में दुनिया भर के सरकारी नीति-निर्माताओं, एआई क्षेत्र के उद्योग विशेषज्ञों, शि्षाविदों, टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।



डिपथीरिया के खिलाफ सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। जेपी नड्डा ने कहा कि भारत ने इप्स, दवाओं और वैक्सीन बनाने में वर्ल्ड लीडर के रूप में स्थापित किया है। इसमें सीआरआई कसौली का बहुत बड़ा

मानहानि मामले में कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे

ठाणे,21 फरवरी 2026।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को मानहानि के एक मामले में भिवंडी में अदालत में पेश हुए। यह मामला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता की ओर से दर्ज कराया गया था। राहुल गांधी ने पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल को अपने नए गारंटर के रूप में पेश किया।



अदालत ने गारंटर बनने की अनुमति दी : सपकाल, पार्टी सांसद वर्षा गायकवाड़ और वकील नारायण अय्यर व कुशल मोर के साथ राहुल गांधी सुबह करीब साढ़े बजे मजिस्ट्रेट अदालत पहुंचे। अदालत ने लोकसभा में विपक्ष के नेता से व्यक्तिगत रूप से पेश होने और नए गारंटर पेश करने को कहा था, क्योंकि पहले के गारंटर (पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल चाकूरकर) का दिसंबर में निधन हो गया था।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे : राहुल गांधी मुंबई में उठे और सड़क मार्ग से भिवंडी जा रहे थे, तभी भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने मुलुंड टोल प्लाजा पर उनके विरोध में काले झंडे दिखाए और नारे लगाए। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि एआई समिट में युवा कांग्रेस के विरोध ने भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया।

संपादकीय



सींचना होगा मातृ भाषाओं का स्वाभिमान

भाषा के साथ खत्म हो जाती है मौलिक सभ्यता

हर वर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है,जो भाषाओं के संरक्षण का संकल्प दिलाता है। इसकी शुरुआत बांग्लादेश के भाषा आंदोलन से हुई थी। मातृभाषा पहचान और संस्कृति का आधार है,लेकिन वैश्वीकरण से कई भाषाएँ विलुप्त हो रही हैं। यूनेस्को के अनुसार,हर दो हफ्ते में एक भाषा गायब होती है। बच्चों की शिक्षा में मातृभाषा का महत्व गांधीजी,टैगोर और कलाम ने भी बताया। भारत की नई शिक्षा नीति भी इसे बढ़ावा देती है...

हर वर्ष 21 फरवरी विश्व में मातृभाषाओं के आहत स्वाभिमान और उसके खोए हुए आत्मविश्वास की वापसी का संकल्प और स्वप्न लेकर आती है। 1999 में यूनेस्को ने इस तिथि को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। यह इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि हम सांस्कृतिक वैविध्य को तभी बचा सकते हैं, जब विभिन्न भाषाओं को बचा पाएँ। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की पृष्ठभूमि पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) के बांग्ला भाषा आंदोलन में निहित है। पाकिस्तान ने उस पर उड़ू थोप दी थी।

इस निर्णय से असंतुष्ट ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों और कुछ सामाजिक संस्थाओं ने 21 फरवरी,1952 को विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलीयां चला दीं। इसमें कई छात्र मारे गए। इन छात्रों की स्मृति में यूनेस्को ने 1999 में इस दिन को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मानने की घोषणा की। उसने मातृभाषा को मंदर टंग के रूप में नहीं,बल्कि मंदर लैंवेंज के रूप में लिया। यानी आपकी मूल भाषा,जिसे प्राथमिक भाषा भी कहा जा सकता है। यह भाषा हमारी पहचान और हमारे मानसिक व्यक्तित्व के निर्माण का आधार होती है।

मातृभाषा का महत्व इसलिए है,क्योंकि हर भाषा की संरचना के सामाजिक-सांस्कृतिक स्रोत होते हैं। भाषा हमें अपने इतिहास,मिथक और परंपरा से जोड़ती है। यह जुड़ाव ही सामूहिक अस्मिता बनकर बेहद मूल्यवान बन जाता है। हमारी संस्कृति की धड़कन हमारी भाषा की अवधारणाओं, मिथकों, बिंबों और प्रत्ययों में मौजूद रहती है, लेकिन विडंबना यह है कि नए वैश्विक परिदृश्य और तेजी से परिवर्तित होती परिस्थितियों में अनेक भाषाएं अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। संघर्षण के नए युग में सांस्कृतिक वैविध्य और अन्य विविधताओं को मिटाकर एक समान संस्कृति,समान सभ्यता और समान रुचियों के ‘विश्व मॉडल’ की संकल्पना ने विकासशील और अल्प विकसित देशों की भाषाओं के समक्ष चुनौतियां पैदा की हैं। विश्व की अनेक भाषाओं पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है।

कई भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर हैं। यूनेस्को का निष्कर्ष है कि हर दो हफ्ते में एक भाषा गायब होती है। शीघ्र ही ऐसा समय आएगा जब लगभग 1500 भाषाएं उपयोगकर्ताओं के अभाव में व्यवहार में नहीं रहेंगी। जब कोई भाषा दम तोड़ती है,तो उसके साथ एक मौलिक संस्कृति,एक मौलिक सभ्यता खत्म हो जाती है।

बच्चों के लिए शिक्षा का सबसे अच्छा माध्यम उनकी मातृभाषा है। अपनी मातृभाषा में बच्चे जल्दी सीखते हैं,लेकिन चिंता की बात है कि विश्व भर में 40 प्रतिशत बच्चे उस भाषा में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, जो भाषा वे घर में बोलते और समझते हैं। इस वर्ष के अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की थीम है-‘बहुभाषी शिक्षा के भविष्य में युवाओं की भूमिका’। गांधीजी ने बच्चों के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा को उसी तरह आवश्यक बताया था, जैसे शारीरिक विकास के लिए मां का दूध।

रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि यदि विज्ञान को जनसुलभ बनाना है, तो मातृभाषा के माध्यम से उसकी शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने शिक्षा का माध्यम को बनाने की परेची करते हुए कहा था कि हमारा मन 13-14 वर्ष की उम्र में ज्ञान का प्रकाश और भाव का रस ग्रहण करने के लिए खुलता है, यदि उसी समय उसके ऊपर पराई भाषा के व्याकरण और शब्दकोश को रटने बाध्यता थोप दी जाए,तो वह सुटुढ़ कैसे रह सकता है? ज्ञात हो कि टैगोर की शिक्षा इंग्लैंड में अंग्रेजी माध्यम से हुई थी। जब उन्होंने विश्वभरती विश्वविद्यालय की संकल्पना की,तो शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा बांग्ला भाषा का चयन किया।

मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण कर सफलता के शिखर पर कैसे पहुंचा जा सकता है, पूर्व राष्ट्रपति डा. एपीजे अब्दुल कलाम इसके सशक्त उदाहरण हैं। उन्होंने कहा था, ‘मैं अच्छे विज्ञानी इसलिए बना, क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा तमिल में प्राप्त की’। अच्छी बात है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के जरिये इस दिशा में पहल की है। प्रारंभिक शिक्षा के लिए मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा के कार्यान्वयन ने शिक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान की है। विश्व के अनेक संपन्न देशों ने अपनी मातृभाषा में ही उन्नति के सोपान पार किए हैं। विज्ञानियों द्वारा यह स्थापित किया जा चुका है कि विश्व में सकल घरेलू उत्पाद में अग्रिम पंक्ति के 20 देश सारा कार्य अपनी मातृभाषा में ही करते हैं। जापान, जर्मनी और फ्रांस के लोगों की अपनी मातृभाषा के प्रति प्रतिबद्धता जगजाहिर है।

हमें समझना होगा कि भाषा मानवीय संस्कृति की टकसाल है। दुनिया की प्रत्येक भाषा अपने आप में एक संस्कृति की कथा संजोए रहती है। हर भाषा शब्द सृष्टि की अनंत संभावनाओं से परिपूर्ण है। इसलिए मातृभाषाओं का स्वाभिमान सींचना होगा। हम सभी भारतीयों का दायित्व है कि हम देश की भाषाई वैविध्य के सौंदर्य को बचाए रखने के लिए मातृभाषा के संरक्षण की दिशा में सार्थक कदम उठाएँ। युवा पीढ़ी में संकल्प जगाएँ कि वे अपनी मातृभाषा को अस्तित्व का कवच मानकर उसकी शक्ति,सामर्थ्य को विस्मृत नहीं होने दें।

एआई के भयंकर दुष्परिणाम हैं...



संजय गोस्वामी
अनुशास्त्रितनगर,मुंबई,

एआई यानि कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है, जो कंप्यूटर को इंसानों की तरह व्यवहार करने में समर्थ बनाती है। इसके द्वारा मशीनों में सोचने,समझने,सीखने, समस्या हल करने और निर्णय लेने संबंधी क्षमताओं का विकास किया जाता है। जॉन मैकार्थी इसके जनक माने जाते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कई फायदे हैं,लेकिन इसके साथ ही इसके गंभीर नुकसान और चुनौतियाँ भी हैं।

एआई के मुख्य नुकसान
नीचे दिए हैं...

- नौकरियों में कमी एआई और स्वचालन के कारण कई पारंपरिक नौकरियां खतरे में हैं। मशीनें इंसानों की तुलना में तेज और बेहतर काम कर सकती हैं,जिससे बेरोजगारी बढ़ने की आशंका है,विशेष रूप से ऐसे काम जिनमें दोहराव अधिक हो।
- भावनाओं और रचनात्मकता का अभाव एआई मशीनें हैं,वे डेटा के आधार पर निर्णय लेते हैं। उनमें इंसानों की तरह भावनाओं, नैतिकता, सहानुभूति और रचनात्मकता का अभाव होता है। वे नई मानवीय समझ



के साथ समस्याओं का हल नहीं निकाल सकती।

- डेटा में पूर्वाग्रह एआई सिस्टम पुराने डेटा से सीखते हैं। यदि त्रेनिंग डेटा में पूर्वाग्रह या असमानताएँ हैं, तो एआई भी पक्षपाती निर्णय ले सकता है। इससे भेदभावपूर्ण परिणाम मिल सकते हैं,जैसे कि भर्ती या ऋा स्वीकृति में अनुचित व्यवहार।
- गोपनीयता और सुरक्षा जोखिम एआई को काम करने के लिए भारी मात्रा में व्यक्तिगत डेटा की आवश्यकता होती है,जिससे डेटा गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है। साथ ही,एआई का उपयोग हैकिंग, डेटा लीक और डीपफेक जैसी भ्रामक चीजें बनाने के लिए किया जा सकता है।
- अत्यधिक निर्भरता लोग निर्णय लेने, सोचने और समस्याओं को हल करने के लिए एआई पर बहुत अधिक निर्भर हो रहे हैं। इससे इंसानों की सोचने की क्षमता और रचनात्मकता में कमी आ सकती है।
- उच्च कार्यान्वयन लागत एआई सिस्टम को विकसित करने, स्थापित करने और बनाए रखने में बहुत अधिक लागत आती है।
- अनपेक्षित परिणाम कभी-कभी एआई एल्गोरिदम अनपेक्षित और गलत परिणाम दे सकते हैं,विशेष रूप से जब वे अप्रत्याशित डेटा का सामना करते हैं,जो वित्तीय या सुरक्षा नुकसान का कारण बन सकते हैं।

8. नैतिक चुनौतियाँ बिना मानवीय हस्तक्षेप के मशीनें जब नैतिक प्रश्नों पर फैसला लेती हैं,तो यह मनुष्य के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है।

9. पर्यावरण पर प्रभाव एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए बहुत अधिक कंप्यूटिंग पावर और पानी की आवश्यकता होती है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है।

अतः हमें मेहनत करना चाहिए बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है और एआई एक किसी चीज को व्यवस्थित करने की तकनीक है जिसका दिमाग मशीन है जो गलत हो हो सकता है कहते हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनके निवास से अखाा करने के लिए दिग्गज ट्रेक कंपनी इष्टोफिक के एआई मॉडल क्लॉग का इस्तेमाल किया था। यह जानकारी वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में निकल कर सामने आई है। इसके बाद से दुनियाभर में इसे सैर्य अभियानों में ए आई के इस्तेमाल की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है लेकिन क्या ए अच्छे किया किसी भी देश के लोकतान्त्रिक तरीके से झूठे हुए राष्ट्रपति का अपहरण करना अच्छे बात है अतः एआई के बहुत से दुष्परिणाम सामने आने वाले है जिसकी समझ इंसानी नहीं है अतः हमें अपने विवेक धैर्य और मेहनत से काम कर ही देश के प्राति में योगदान देना चाहिए इसलिए एआई कृत्रिम बुद्धि है लेकिन मानव को बुद्धि ईश्वर ने दि है समय के लिए इसलिए इस पर ज्यादा प्रेकस करने के बजाय मेहनत और लगन से काम करना चाहिए,सफलता हेतु मेहनत के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इंसान का दिमाग को मशीन से नहीं जोड़ा जा सकता है क्योंकि इंसान ईश्वर की कृति है जबकी मशीन इंसान की बनाई गई टेक्नोलॉजी है।

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा उरतुम

ठाकुर शिवपाल सिंह उर्फ छोटे महाराज इन दिनों थोड़े विचलित थे। विचलन का कारण कोई आध्यात्मिक संकट नहीं था, बल्कि गाँव की मुख्य से क पर बना वह गड्ढा था जिसे स्थानीय लोग श्रद्धावश मिनी-मानसरोवर कहने लगे थे। छोटे महाराज का मानना था कि लोकतंत्र का पहिया इसी गड्ढे में आकर पंचर हो जाते है,और जब तक पहिया पंचर न हो, शासन की गरिमा समझ में नहीं आती। गड्ढे की गहराई मापने के लिए किसी फीते की जरूरत नहीं थी। उसमें जब कोई साइकिल सवार गिरता और उसके मुँह से जो गलियाँ निकलतीं, उनकी तोत्रता से गड्ढे की भयावहता का अंदाजा लग जाता था।

ब्लॉक ऑफिस में बैठे गुप्ता जी फाइलों के उस ढेर के पीछे छिपे थे जिसे वह अपना सुखा था। सरकारी तंत्र में फाड़लें वैसे ही अमर होती हैं जैसे आत्मा,न इन्हें आग जला सकती है,न पानी भिगो सकता है,बस एक विभाग से दूसरे विभाग में इनका पुनर्जन्म होता रहता है। जब छोटे महाराज ने गड्ढे की शिकायत की,तो गुप्ता जी ने चरमा उतारकर ऐसे देखा जैसे किसी ने भरे दरबार में उनसे उनकी जायदाद पूछ ली हो। उन्होंने बड़े धैर्य से समझाया कि गड्ढा होना समस्या नहीं है,समस्या है उसका प्रविजन। बजट में सड़क बनाने का प्रावधान है, उसे सुधारने का नहीं। अगर सुधार दिया गया, तो नया टैंडर कैसे आएगा? और अगर नया टैंडर नहीं आएगा, तो विभाग के बच्चों की दीवाली फीकी रह जाएगी। यह तर्क इतना मानवीय था कि छोटे महाराज की नैतिकता वहीं ढेर हो गई।

उधर गाँव की चौपाल पर बहस छिड़ी थी कि विकास बड़ा है या भ्रष्टाचार। गयादीन ने बीड़ी का कश खींचते हुए कहा कि भ्रष्टाचार तो शुद्ध घी की तरह है-दिखता नहीं,पर अगर दाल में न हो तो स्वाद नहीं आता। अब देखो,प्रधान



जी ने नाली बनवाई। नाली ऐसी बनी है कि पानी ढलान की तरफ जाने के बजाय वापस प्रधान जी के घर की तरफ आता है। इसे कहते हैं—जड़ों की ओर वापसी। भीड़ में से किसी ने चुटकी ती की सड़क का क्या होगा? इस पर गयादीन हँसा और बोला कि सड़क तो उस सती-सावित्री की तरह है जिसे हर पांच साल में चुनाव के वक्त नया श्रृंगार मिलता है,बाकी समय वह धूल फांकती है ताकि वोटरों को अपनी औकात याद रहे। अगर सड़क चकाचक हो जाएगी,तो लोग खुद को कलेक्टर समझने लेंगेंगे। लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए जनता का थोड़ा परेशान रहना अनिवार्य है।

शाम होते-होते गड्ढे के पास एक सरकारी बोर्ड लगा दिया गया। बोर्ड पर लिखा था—सावधान! आगे विकास कार्य प्रगति पर है। गाँव वाले खुश थे। काम भले न हो रहा हो,पर प्रगति शब्द में एक ऐसी जादुई महक होती है जो फटे हाल आदमी को भी सुनहरे भविष्य के सपने दिखा देती है। छोटे महाराज ने भी अपनी लाठी उठाई और घर की ओर चल दिए। उन्हें समझ आ गया था कि इस देश में गड्ढे भरे नहीं जाते, उनके चारों तरफ एक ऐसी शब्दावली बुन दी जाती है कि लोग गड्ढे को ही विशिष्ट डिजाइन समझने लगते हैं। सड़क अब भी टूटी थी,लेकिन फाड़लों में वह आदर्श मार्ग घोषित हो चुकी थी। भारत के इस हिस्से में सत्य वही है जो कागज पर दर्ज है,बाकी सब तो मात्रा एक माया है।

भारत का एआई नेतृत्व तकनीक एवं मानवीय मूल्यों का संगम बने



ललित गर्ग
पटपटड़ाज,दिल्ली-92

दिल्ली इन दिनों केवल भारत की राजनीतिक राजधानी भर नहीं,बल्कि उभरती तकनीकी चेतना का वैश्विक केंद्र बनी हुई है।'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब प्रयोगशालाओं या कॉरपोरेट दफ्तरों तक सीमित तकनीक नहीं रही,बल्कि वह विकास की नई परिभाषा गढ़ने की दिशा में अग्रसर है। दुनिया के विभिन्न देशों, तकनीकी कंपनियों,शोध संस्थानों और नीति-निर्माताओं की उपस्थिति ने इस सम्मेलन को वैश्विक विमर्श का मंच बना दिया है। विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों की भूमिका यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। हमें ऐसे संस्थानों की आवश्यकता है जो वास्तविक शोध और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें,न कि केवल झूठे दावों और विज्ञापन के बल पर प्रतिष्ठ अर्जित करने का प्रयास करें। शिक्षा में पारदर्शिता और गुणवत्ता ही उस आधारशिला को मजबूत करेगी जिस पर भारत का एआई भविष्य खड़ा होगा। यह सवाल उठता जा रहा है कि भारत आज व्यवहार में एआई व रोबोटिक्स के अनुसंधान में कहां खड़ा है? आखिर ग्लोबेटिया यूनिवर्सिटी के नीति-निर्याताओं ने यह क्यों नहीं सोचा कि चीन निर्मित एक रोबोट को अपनी उपलब्धि बताने से देश की प्रतिष्ठा को आंच आएगी?अब यूनिवर्सिटी की तरफ से सफाई दी जा रही है कि

संभावनाएँ खोल रहा है। ऐसे समय में भारत का दृष्टिकोण केवल तकनीकी उन्नति तक सीमित नहीं,बल्कि वह इसे मानव-केंद्रित विकास के साथ जो ने का प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि तकनीक का अंतिम लक्ष्य मानवता की सेवा होना चाहिए,न कि केवल लाभ और वर्चस्व की दौड़।

भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी युवा आबादी है। यदि इस ऊर्जा को गणित,भौतिकी, कंप्यूटर विज्ञान और ढाटा विज्ञान जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाए तो भारत एआई अनुसंधान और नवाचार में विश्व की अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो सकता है। विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों की भूमिका यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। हमें ऐसे संस्थानों की आवश्यकता है जो वास्तविक शोध और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें,न कि केवल झूठे दावों और विज्ञापन के बल पर प्रतिष्ठ अर्जित करने का प्रयास करें। शिक्षा में पारदर्शिता और गुणवत्ता ही उस आधारशिला को मजबूत करेगी जिस पर भारत का एआई भविष्य खड़ा होगा। यह सवाल उठता जा रहा है कि भारत आज व्यवहार में एआई व रोबोटिक्स के अनुसंधान में कहां खड़ा है? आखिर ग्लोबेटिया यूनिवर्सिटी के नीति-निर्याताओं ने यह क्यों नहीं सोचा कि चीन निर्मित एक रोबोट को अपनी उपलब्धि बताने से देश की प्रतिष्ठा को आंच आएगी?अब यूनिवर्सिटी की तरफ से सफाई दी जा रही है कि



उसने रोबोट की निर्माण का दावा नहीं किया। वहीं दूसरी ओर उन सरकारी अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की जानी चाहिए, जिन्होंने बिना जांच-पड़ताल के विश्वविद्यालय को एआई समिट में स्टॉल लगाने की अनुमति क्यों दी। निश्चित रूप से भारत ने पिछले कुछ वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीक व रोबोटिक उत्पादन के क्षेत्र में ऊंची छ्छांग लगाई है। युवा शक्ति के देश भारत ने एआई के क्षेत्र में अमेरिका व चीन के बाद अपना तीसरा स्थान बनाया है। जिसकी पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थाओं ने भी की है। लेकिन एक विरोधाभासी हकीकत यह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ी आबादी का देश है,जहां श्रम शक्ति प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई की भूमिका क्रांतिकारी सिद्ध हो सकती है। रोगों की प्रारंभिक पहचान,सटीक निदान,दवाओं के शोध और ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन सेवाओं के विस्तार में एआई नई संभावनाएँ लेकर आया है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में जहाँ

स्वास्थ्य संसाधनों का असमान वितरण है,वहाँ एआई आधारित समाधान दूरस्थ क्षेत्रों तक बेहतर सेवाएँ पहुँचाने में सहायक हो सकते हैं। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में मौसम पूर्वानुमान,मृदा विश्लेषण, फसल प्रबंधन और आपूर्ति श्रृंखला के अनुकूलन में एआई किसानों की आय बढ़ाने और जोखिम कम करने का माध्यम बन सकता है। जलवायु परिवर्तन के देश भारत ने एआई की प्रभावित कर रहे हैं। एआई आधारित मॉडलिंग और डेटा विश्लेषण से प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान, संसाधनों का बेहतर प्रबंधन और टिकाऊ नीतियों का निर्माण संभव हो सकता है। यदि भारत इन क्षेत्रों में एआई का प्रभावी उपयोग करता है तो वह वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए एक मार्गदर्शक मॉडल प्रस्तुत कर सकता है।

शासन और आर्थिक विकास के क्षेत्र में भी एआई पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने का माध्यम बन सकता है।

इसलिए आवश्यक है कि एआई के विकास के साथ नैतिक ढाँचे और नियामक व्यवस्था भी सुदृढ़ हो। भारत को ऐसा मॉडल विकसित करना होगा जिसमें नवाचार की स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व का संतुलन बना रहे। मानवता केंद्र में का सिद्धांत केवल नारा न बने,

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विशेष अभियान चलाकर तंबाकू से जुड़े तथ्यांकित तैलमर के भ्रम को तोड़ना भी समय की मांग है। फिल्मों, सोशल मीडिया और साधियों के प्रभाव के कारण कई युवा इसे आधुनिकता का प्रतीक समझ बैठते हैं। इस मानसिकता को बदलने के लिए जागरूकता अभियान आवश्यक हैं।

एसा ही मॉडल केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित न रहकर मध्य प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों में लागू किया जाना चाहिए।

एसा ही मॉडल केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित न रहकर मध्य प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों में लागू किया जाना चाहिए।

एसा ही मॉडल केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित न रहकर मध्य प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों में लागू किया जाना चाहिए।

एसा ही मॉडल केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित न रहकर मध्य प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों में लागू किया जाना चाहिए।

एसा ही मॉडल केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित न रहकर मध्य प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों में लागू किया जाना चाहिए।

एसा ही मॉडल केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित न रहकर मध्य प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों में लागू किया जाना चाहिए।

एसा ही मॉडल केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित न रहकर मध्य प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों में लागू किया जाना चाहिए।

एसा ही मॉडल केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित न रहकर मध्य प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों में लागू किया जाना चाहिए।

एसा ही मॉडल केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित न रहकर मध्य प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों में लागू किया जाना चाहिए।

बल्कि नीति और व्यवहार में परिलक्षित हो। एआई का उपयोग यदि समावेशी विकास, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय के लिए किया जाए तो यह तकनीक समाज के कमजोर वर्गों के लिए अवसरों का द्वार खोल सकती है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो चीन और अमेरिका एआई के क्षेत्र में तीव्र प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। भारत के सामने चुनौती यह है कि वह इस दौड़ में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए। भारत का लोकतान्त्रिक ढाँचा, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और विशाल बाजार उसे एक अलग सामर्थ्य प्रदान करते हैं। यदि वह अनुसंधान में निवेश,स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के सुदृढ़ीकरण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्राथमिकता दे तो वह एआई के क्षेत्र में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए सस्ती,सुलभ और मानव-केंद्रित तकनीक उपलब्ध कराकर भारत एक नैतिक नेतृत्व स्थापित कर सकता है।

‘इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026’ इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सम्मेलन केवल विचारों का आदान-प्रदान नहीं, बल्कि भविष्य की संरचना का प्रारूप है। यहाँ से निकले संकल्प यदि नीति और क्रियान्वयन में रूपांतरित होते हैं तो भारत तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा सकेगा। यह अवसर है कि हम एआई को केवल आर्थिक लाभ का साधन न मानें,बल्कि उसे सामाजिक परिवर्तन और मानव कल्याण के माध्यम के रूप में देखें।



करना और दो दुकानों के बीच कम से कम 500 मीटर की दूरी सुनिश्चित करने पर विचार करना भी प्रभावी कदम हो सकता है। इससे तंबाकू उत्पादों की आसान उपलब्धता पर अंकुश लगेगा। बिना वैध लाइसेंस के बिक्री को कठिन बनाना अवैध कारोबार पर रोक लगाने में सहायक सिद्ध होगा। यदि इन नियमों का कठोरता से पालन हो, तो तंबाकू की खपत में निश्चित रूप से कमी लाई जा सकती है।

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विशेष अभियान चलाकर तंबाकू से जुड़े तथ्यांकित तैलमर के भ्रम को तोड़ना भी समय की मांग है। फिल्मों, सोशल मीडिया और साधियों के प्रभाव के कारण कई युवा इसे आधुनिकता का प्रतीक समझ बैठते हैं। इस मानसिकता को बदलने के लिए जागरूकता अभियान आवश्यक हैं।

एसा ही मॉडल केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित न रहकर मध्य प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों में लागू किया जाना चाहिए।

एसा ही मॉडल केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित न रहकर मध्य प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों में लागू किया जाना चाहिए।

एसा ही मॉडल केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित न रहकर मध्य प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों में लागू किया जाना चाहिए।

एसा ही मॉडल केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित न रहकर मध्य प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों में लागू किया जाना चाहिए।

एसा ही मॉडल केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित न रहकर मध्य प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों में लागू किया जाना चाहिए।

एसा ही मॉडल केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित न रहकर मध्य प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों में लागू किया जाना चाहिए।

एसा ही मॉडल केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित न रहकर मध्य प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों में लागू किया जाना चाहिए।

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के उपरांत मतदाता सूची प्रकाशित

- राजनीतिक दलों को प्रदाय की गई प्रकाशित मतदाता सूची
- कुल 6,02,310 मतदाता पंजीकृत, 3,818 की वृद्धि दर्ज

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 21 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत वसंत की अध्यक्षता में आज कलेक्टर सभाकक्ष में जिले के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के तहत प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वसंत ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर के निर्देशानुसार 27 अक्टूबर 2025 से जिले में निर्वाचक नामावतियों का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान प्रारंभ किया गया था। अहंता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर चार माह तक निरंतर एवं चरणबद्ध रूप से संचालित इस अभियान के पश्चात 21 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है।

घर-घर सत्यापन एवं डिजिटलीकरण

विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 782 बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों का वितरण एवं सत्यापन कार्य संपादित किया गया। कुल 6,74,980 मतदाताओं का मिलान एवं मैपिंग कार्य पूर्ण किया गया तथा प्राप्त 5,98,492 गणना प्रपत्रों का शत-प्रतिशत डिजिटलीकरण सुनिश्चित किया गया। सर्वेक्षण के दौरान मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित एवं दो स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं की पहचान कर आवश्यक संशोधन किए गए। जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए, उनकी पुष्टि हेतु बीएलओ एवं संबंधित राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित की गईं। संपूर्ण जानकारी जिला प्रशासन एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किए गए।

प्रमुख आंकड़े

झाफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के उपरांत 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की गईं, जिनका निराकरण 14 फरवरी 2026 तक नियमानुसार किया गया। कुल पंजीकृत मतदाता (21 फरवरी 2026) 6,02,310, झाफ्ट प्रकाशन के बाद 3,818 वृद्धि हुई है। प्रारंभिक मतदाता संख्या (27 अक्टूबर 2025) - 6,74,980 थी। झाफ्ट प्रकाशन (23 दिसंबर 2025) - 5,98,492 मतदाता थे।

पारदर्शिता एवं सहयोग : विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान नागरिकों से प्राप्त नवीनतम फोटोग्राफ को भी अंतिम मतदाता सूची में अद्यतन किया गया है। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अंतिम मतदाता सूची की दो प्रतियां (एक फोटोयुक्त मुद्रित एवं एक फोटोरहित सॉफ्ट कॉपी) नि:शुल्क उपलब्ध कराई गई हैं। इस अभियान को समयसीमा में सफलतापूर्वक पूर्ण करने हेतु 03 निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, 48 सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, 876 बीएलओ एवं 1564 बूथ लेवल एजेंट बीएलए) सहित

अनेक अधिकारी-कर्मचारियों एवं स्वयंसेवकों की सक्रिय सहभागिता रही। मीडिया एवं नागरिक समाज का भी महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ।

विधानसभावार अंतिम मतदाता सूची का आंकड़े

विधानसभा लुण्ड्रा (09) झाफ्ट मतदाता 1,86,699, जुड़े 1379, विलोपन 246, वृद्धि 1,133
अंतिम मतदाता 1,86,832 हुए
विधानसभा अम्बिकापुर (10) झाफ्ट मतदाता 2,25,649, जुड़े 2,598, विलोपन 884, वृद्धि 1714, अंतिम मतदाता 2,27,363 हुए हैं। विधानसभा सोतापुर (11) झाफ्ट मतदाता 1,87,144, जुड़े 1015, विलोपन 44, वृद्धि 971, अंतिम मतदाता 1,88,115 हुए हैं।



मतदाता नाम जाँच एवं आवश्यक प्रपत्र

जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वसंत ने बताया कि 01.01.2026 की पात्रता तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा भी प्रपत्र संख्या 6 भरकर भविष्य में प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। भविष्य में समय-समय पर होने वाले आवश्यक संशोधनों के अनुसार, नागरिक प्रपत्र संख्या 6, 7 और 8 भी भर सकेंगे। दौरान आगामी अहंता तिथि 01/10/2026 के संदर्भ में भावी मतदाताओं से आवेदन प्रपत्र 6 में प्राप्त किया गया है। सभी मतदाता अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम नीचे दिए गए माध्यमों से जाँच सकते हैं- <https://ceochhattisgarh.nic.in>, वोटर पोर्टल- <https://voters.eci.gov.in>, ECINETAPP, बीएलओ के माध्यम से अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय / ERO / AERO कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अजीत वसंत ने जिले के सभी नागरिकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, बीएलओ, बीएलए एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र की सुदृढ़ आधारशिला है। यदि पात्र मतदाता का नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म-6 भरकर उसके साथ घोषणा पत्र और आवश्यक सहायक दस्तावेज सलग कर ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अंतिम मतदाता सूची में दी गई जानकारी में कोई त्रुटि एवं स्थानांतरण हेतु फॉर्म-8 भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है। कलेक्टर ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की कि वे अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम अनिवार्य रूप से जाँच लें, ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे। बैठक में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुनील नायक, एसडीएम श्री फ़नेश सिन्हा तथा निर्वाचन शाखा के कर्मचारी उपस्थित थे।

साले की शादी में आया दामाद बना हत्यारा सो रही पत्नी, साली और मासूम पर हथौड़े से हमला, पत्नी की मौत

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 21 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

सूरजपुर जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सरहरी में साले की शादी में ससुराल आए एक युवक ने आधी रात को पत्नी, साली और उसकी मासूम बेटी पर हथौड़े से जानलेवा हमला कर दिया। घटना में पत्नी की मौत हो गई, जबकि साली की हालत गंभीर है। मासूम बच्ची का इलाज जारी है। पुलिस ने आरोपी को सनावल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के अनुसार, यशोदा कुशवाहा (35) पति गणेश कुशवाहा, निवासी ग्राम रेवटी थाना चंदोरा, अपने भाई सुरेश की शादी में पति और बेटी के साथ ग्राम सरहरी आई थीं। 20 फरवरी को रागत लौटने के बाद अधिकांश रिश्तेदार चले गए थे, लेकिन यशोदा अपने पति व बेटी के साथ रुक गई थीं। रात करीब 2 बजे गणेश कुशवाहा उठा और कमरे में सो रही पत्नी यशोदा के सिर पर हथौड़े से हमला कर दिया। इसके बाद वह दूसरे कमरे में गया और वहां सो रही साली गंगोत्री तथा उसकी बेटी पंकी पर भी वार कर दिया। अचानक हुई इस घटना से घर में चीख-पुकार मच गई। परिजन जब कमरे में पहुंचे तो तीनों गंभीर हालत में



खून से लथपथ पड़ी थीं। तत्काल उन्हें प्रतापपुर अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को अंबिकापुर रेफर कर दिया गया।

मिशन अस्पताल में महिला को मृत घोषित : परिजन तीनों को अंबिकापुर स्थित मिशन अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां जांच के दौरान डॉक्टरों ने यशोदा को मृत घोषित कर दिया। गंगोत्री की हालत गंभीर होने पर उसे रायपुर रेफर किया गया है। वहीं मासूम पंकी का इलाज मिशन अस्पताल में चल रहा है। वारदात के बाद आरोपी गणेश कुशवाहा फरार हो गया था। घटना की सूचना मिलते ही प्रतापपुर पुलिस सक्रिय हुई और तलाश शुरू की। पुलिस ने आरोपी को बलरामपुर जिले के सनावल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मोमिनपुरा में हड़कंप, पीलिया के बढ़ते मामलों से प्रशासन सतर्क 42 से अधिक लोग संक्रमित, ज्यादातर बच्चे, पाइप लाइन लीकेज पर उठे सवाल

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 21 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

शहर के मोमिनपुरा स्थित वार्ड क्रमांक 40-41 में दूषित पानी के सेवन से पीलिया फैलने का मामला सामने आया है। अब तक 42 से अधिक लोग पीलिया पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें अधिकांश बच्चे शामिल हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम प्रशासन में हड़कंप मच गया है। शनिवार को दोनों विभागों की टीमों ने क्षेत्र में पहुंचकर सर्वे और सैपलिंग का कार्य शुरू किया।

जानकारी के अनुसार क्षेत्र में पीलिया का पहला मामला तीन माह पूर्व सामने आया था। दिसंबर में चार वर्षीय बालक मो. अवेश में पीलिया की पुष्टि हुई थी। इसके बाद धीरे-धीरे आसपास के बच्चों में संक्रमण फैलने लगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि तीन माह के भीतर 20 से 25 बच्चे पीलिया की चपेट में आए। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के



अनुसार अब तक कुल 42 लोग संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने क्षेत्र के 10 घरों से पानी के नमूने लेकर जांच के लिए मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग भेजे थे। जांच में कुछ नमूनों में 22 से 28 एमपीएन प्रति 100 एमएल तक बैक्टीरियल लोड पाया गया, जो पीने योग्य मानक से

अधिक है। माइक्रोबायोलॉजी विभाग के अनुसार क्लोरीनयुक्त पानी में एमपीएन की मात्रा शून्य होनी चाहिए। 10 से अधिक एमपीएन को संदिग्ध और 50 से अधिक को अत्यधिक प्रदूषित माना जाता है। रिपोर्ट मिलने के बाद सीएमएचओ ने नगर निगम को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

संयुक्त टीम कर रही सर्वे : दूषित पानी की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम ने क्षेत्र में सर्वे शुरू किया है। स्वास्थ्य विभाग ने 20 से अधिक लोगों के सैपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे हैं।

साथ ही लोगों को उबला हुआ पानी पीने की सलाह दी गई है। नगर निगम की टीम दूषित पानी के स्रोत की जांच में जुटी है और घर-घर से पानी के नमूने एकत्र कर रही है। वार्ड पार्थद मो. हसन ने बताया कि जांच के दौरान तीन स्थानों पर पाइप लाइन में लीकेज मिला है। शाहीद हमीद चौक, आर्यू होटल के नीचे और पॉपुलर के सामने पाइप लाइन से पानी रिस रहा है। आशंका है कि इन्हीं लीकेज के कारण सफाई का पानी दूषित हुआ। पार्थद का कहना है कि पूर्व में भी निगम प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई थी, लेकिन समय पर सुधार नहीं किया गया। वर्तमान में भी लीकेज पूरी तरह दुरुस्त नहीं हो पाया है।

गांधी चौक से रेलवे स्टेशन तक 5.54 किमी सड़क निर्माण को 61.34 करोड़ की मंजूरी, मार्किंग शुरू...



—संवाददाता—

अम्बिकापुर, 21 फरवरी 2026 (घटती-घटना)। शहरवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य शासन ने वर्ष 2025-26 के बजट में शामिल गांधी चौक से रेलवे स्टेशन तक 5.54 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण एवं फोरलेन निर्माण कार्य के लिए 61 करोड़ 34 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस मार्ग का निर्माण एवं उन्नयन कार्य किया जाएगा। प्रस्तावित योजना के तहत सड़क को लाम्पा 12-12 मीटर चौड़ा किया जाएगा। साथ ही डिवाइडर, नाली निर्माण, फुटपाथ, विद्युत लाइटिंग एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं भी विकसित की जाएगी। इस महत्वपूर्ण मार्ग के उन्नयन से शहर में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। गांधी चौक से रेलवे स्टेशन तक प्रतिदिन भारी यातायात रहता है, जिससे जाम की समस्या बनी रहती है। सड़क के चौड़ीकरण के बाद आवागमन सुगम होगा और व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार कार्य की निविदा प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। शहरवासियों ने इस स्वीकृति का स्वागत करते हुए इसे अम्बिकापुर के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है।

प्रशासनिक दक्षता हेतु जिले के 83 हल्का पटवारियों का स्थानांतरण

कलेक्टर ने पटवारियों का स्थानांतरण आदेश किया जारी

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 21 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने प्रशासनिक कार्यों में दक्षता, पारदर्शिता एवं लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ 83 हल्का पटवारियों का स्थानांतरण आदेश जारी किया है। जारी आदेश क्रमांक 277/अ.भू.अ/ पट.अ/ 2026 दिनांक 21 फरवरी 2026 के अनुसार उक्त स्थानांतरण छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता एवं छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख नियमावली (भाग-1) के नियम 7(2) तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर के पत्र क्रमांक एफ-2-48/सात-2/2014 दिनांक 12 सितम्बर 2014 में उल्लेखित राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-पांच-क्रमांक-1 की कड़िका-16 के प्रावधानों के तहत किए गए हैं। आदेश के तहत संबंधित पटवारियों को आगामी आदेश पर्यंत पदस्थ किया गया है। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि सभी स्थानांतरित पटवारी तत्काल प्रभाव से नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, जिससे राजस्व संबंधी कार्यों का सुचारु संचालन एवं आमजनो को त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।



प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरगीडीह हुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नत लुण्ड्रा विधायक ने मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरि झंडी दिखाकर किया रवाना

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 21 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

जिले के विकासखण्ड लुण्ड्रा के अंतर्गत ग्राम बरगीडीह में आज स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरगीडीह का उन्नयन कर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में लोकार्पित किया गया। साथ ही पी.एम. जनमन कार्यक्रम के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर लुण्ड्रा विधायक प्रबोध मिंज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष निरुपा सिंह ने की। विशिष्ट अतिथियों में जिला पंचायत उपाध्यक्ष देवनारायण यादव, सतीश जायसवाल, संजय गुप्ता, बी.डी.सी. मो. हलीम फिरदौसी, जयंतनाथ सिंह, जनपद सदस्य कुसुम कांता, सरपंच बरगीडीह संगीता पैकरा, सरपंच खाराकोना तुलेश्वर पैकरा सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पी. एस. मावों एवं खण्ड चिकित्सा अधिकारी धीरपुर डॉ.



राघवेन्द्र चौबे सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। विधायक श्री प्रबोध मिंज ने अपने संबोधन में कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में उन्नयन से क्षेत्रवासियों को बेहतर एवं विस्तृत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। आने वाले समय में स्टॉफ की संख्या में वृद्धि एवं विशेषज्ञ सेवाओं के विस्तार से स्थानीय ग्रामीणों को जिला अस्पताल तक लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता कम होगी। उन्होंने क्षेत्र में सड़क, पुल-पुलिया निर्माण, हायर सेकेंडरी स्कूल स्थापना तथा विभिन्न

स्थानों पर एनीकेट निर्माण जैसे विकास कार्यों की भी जानकारी दी।

पी.एम. जनमन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभ की गई मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से विकासखण्ड लुण्ड्रा के दूरस्थ एवं पहुंचविहीन आदिवासी अंचलों में नियमित स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएंगी। इससे ग्रामीणों को उनके ग्राम स्तर पर ही जांच, परामर्श एवं प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

अंबिकापुर में भाजपा की जिला कार्यशाला संपन्न...प्रशिक्षण वर्ग की रूपरेखा पर मंथन, एआई उपयोग से लेकर विकसित भारत संकल्प तक चर्चा

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 21 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यशाला का आयोजन शनिवार को संकल्प भवन स्थित भाजपा कार्यालय में किया गया। बूथ, मंडल और जिला स्तर पर प्रस्तावित प्रशिक्षण वर्गों की तैयारी को लेकर आयोजित इस कार्यशाला में अपेक्षित पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में कुल पाँच सत्र आयोजित किए गए। कार्यशाला की अध्यक्षता सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने की। उद्घाटन सत्र में भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने प्रशिक्षण वर्ग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संगठन की मजबूती के लिए नियमित प्रशिक्षण आवश्यक है। द्वितीय सत्र की अध्यक्षता महापौर मंजूषा भगत ने की। विषय वक्ता अंबिकेश केशरी ने प्रशिक्षण वर्ग की तिथि, स्थान, विषय-वस्तु तथा जिला व मंडल स्तर के वक्ताओं की सूची की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय-सीमा में सभी स्तरों पर प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। तृतीय सत्र महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री फुलेस्वरी



सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। सोशल मीडिया प्रदेश सह संयोजक ज्ञान प्रकाश दुबे ने पीपीटी के माध्यम से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एआई के उपयोग, मीडिया प्रबंधन और सोशल मीडिया कंटेंट निर्माण पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बदलते दौर में डिजिटल दक्षता संगठन के लिए आवश्यक है।

‘पंच परिवर्तन’ और विकसित भारत का संकल्प : चौथे सत्र की अध्यक्षता सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी ने की। आरएसएस के विभाग प्रचारक हेमंत नाग ने ‘पंच परिवर्तन’ विषय पर कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक कर्तव्य बोध और स्वावलंबन पर विस्तार से विचार रखे। उन्होंने

कहा कि 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए राष्ट्रवादी सोच आवश्यक है।

जिज्ञासा समाधान के साथ समापन अंतिम सत्र में जिला पंचायत अध्यक्ष निरुपा सिंह की अध्यक्षता में जिज्ञासा समाधान किया गया। भारत सिंह सिसोदिया ने आगामी प्रशिक्षण वर्गों की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की। कार्यक्रम की शुरुआत पंजीयन और ध्वजारोहण से हुई। भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पजलि अर्पित की गई। सत्र अध्यक्ष और वक्ताओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर आधारित पुस्तक भेंट कर सम्मानित किया गया।

153 करोड़ की विकास सौगात के साथ मुख्यमंत्री का कोरिया दौरा ऐतिहासिक जिला पंचायत अध्यक्ष मोहित राम पैकरा ने जताया आभार,कहा...जिले के विकास को मिली नई दिशा

—संवाददाता—
बैकुंठपुर, 21 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

दो दिवसीय कोरिया जिला प्रवास पर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिले को 153 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात प्रदान की। अपने प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं घोषणा की, साथ ही कोरिया उत्सव का शुभारंभ भी किया, मुख्यमंत्री द्वारा की गई विकास घोषणाओं पर जिला पंचायत अध्यक्ष मोहित राम पैकरा ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह कोरिया जिले के लिए ऐतिहासिक क्षण है, जिससे आधारभूत संरचना, पर्यटन, कानून-व्यवस्था और ग्रामीण संपर्क को नई मजबूती मिलेगी।

आगमन के साथ संवेदनशीलता का संदेश

कोरिया पहुंचते ही मुख्यमंत्री ने सबसे पहले मौसा बंदी डॉ. घोष के निवास पर जाकर उनसे सौजन्य भेंट की। यह पहली बार बताया गया कि किसी मुख्यमंत्री ने स्वयं उनके घर जाकर मुलाकात की, इसके बाद मुख्यमंत्री सरभोका पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व

कानून-व्यवस्था और यातायात को मजबूती

कोरिया उत्सव के मंच से मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लिए—पोड़ी बचरा पुलिस चौकी को थाना का दर्जा, पांडवपारा पुलिस सहायता केंद्र को पुलिस चौकी में उन्नयन इसके अलावा, लंबे समय से प्रतीक्षित सलका बाईपास के लिए 18 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे शहर में यातायात का दबाव कम होने की संभावना है।

लोक निर्माण विभाग और पर्यटन विकास

जिला पंचायत अध्यक्ष स्व. फलेंद सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

सरभोका में विकास की घोषणाएं...

सरभोका में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की—मिनी स्टेडियम अधोसंरचना एवं खेल सामग्री के लिए 25 लाख रुपये, अहिरापारा नाला पर पुल निर्माण हेतु 15 लाख रुपये, कूड़ेली बाजार कंक्रीटीकरण के लिए 20 लाख रुपये इन घोषणाओं से स्थानीय युवाओं को खेल सुविधाएं, ग्रामीणों को बेहतर आवागमन और व्यापारियों को सुदृढ़ बाजार व्यवस्था मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

सड़क संपर्क को मिली गति

ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क मार्गों के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री ने—सोनहत के कुशहा से घुघरा मार्ग (3 किमी) के निर्माण हेतु 6 करोड़ रुपये, बैकुंठपुर के छिंदिया से रामपुर शिवपुर मार्ग (4 किमी, पुल-पुलिया सहित) के लिए 8 करोड़ रुपये, की स्वीकृति प्रदान की। इन सड़कों से ग्रामीण अंचलों में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं व्यापारिक गतिविधियों को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

कोरिया उत्सव का शुभारंभ

मुख्यमंत्री ने कोरिया उत्सव का भी शुभारंभ किया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विकास प्रदर्शनी के माध्यम से जिले की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में नागरिक, जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे।



जिला पंचायत अध्यक्ष का आभार

विकास की नई दिशा

जिला पंचायत अध्यक्ष मोहित राम पैकरा ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणाएं कोरिया जिले के समग्र विकास के लिए मील का पत्थर साबित होंगी, उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए आशा व्यक्त की कि सभी योजनाएं शीघ्र धरातल पर उतरेगी और जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री का यह दो दिवसीय प्रवास केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि विकास की ठोस रूपरेखा के साथ कोरिया जिले को नई ऊर्जा देने वाला साबित हुआ, आधारभूत संरचना, पर्यटन, खेल, कानून-व्यवस्था और ग्रामीण संपर्क के क्षेत्र में की गई घोषणाएं आने वाले समय में जिले के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को बदल सकती हैं, कोरिया जिला अब विकास की एक नई यात्रा की ओर अग्रसर होता दिखाई दे रहा है।

हाईस्कूल मुख्य परीक्षा 2026 का हिन्दी विषय पेपर शांतिपूर्वक संपन्न कुल 9637 पंजीकृत परीक्षार्थीयों में 9359 हुए शामिल....



—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 21 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर द्वारा संचालित हाईस्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा 2026 अंतर्गत दिनांक 21 फरवरी 2026 को हिन्दी विषय की परीक्षा जिले के 75 परीक्षा केन्द्रों में सफलतापूर्वक एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। कलेक्टर श्री अजीत वसंत द्वारा गठित उड़नदस्ता दल ने विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण किए गए प्रमुख केन्द्रों में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केदारपुर, कन्या दरिमा, बालक दरिमा, सखौली, धौरपुर, जोरी, डूमरडीह, पडौली, पुहुपुटा, कन्या लखनपुर, उदयपुर, कन्या सीतापुर, प्रतापगढ़, बालक बतौली, कन्या बतौली, क्रिश्चियन सूर्यापारा सीतापुर एवं डी. हिलाउस पब्लिक स्कूल अम्बिकापुर शामिल हैं। इसी प्रकार जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा गठित उड़नदस्ता दल ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खलिबा, गांधीनगर,

कन्या शिक्षा परिसर केदारपुर, सेंट जेवियर्स एवं होलीक्रास कॉन्वेंट विद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान परीक्षा व्यवस्था संतोषजनक पाई गई। सभी केन्द्रों में परीक्षा निर्धारित समयानुसार, शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित रूप से संचालित होना पाया गया।

जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बिकापुर द्वारा होलीक्रास कॉन्वेंट विद्यालय के प्राचार्य को निर्देशित किया गया कि विद्यार्थियों के आधार आईडी, जन्म प्रमाण पत्र, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र शत-प्रतिशत तैयार कराना सुनिश्चित करें, जिससे विद्यार्थियों को भविष्य में किसी प्रकार की प्रशासनिक असुविधा का सामना न करना पड़े। हाईस्कूल परीक्षा से संबंधित पंजीकृत कुल 9637 परीक्षार्थी थे जिसमें परीक्षा में 9359 सम्मिलित हुए, वहीं 278 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे जिला प्रशासन द्वारा परीक्षा की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक व्यवस्था की गई थी। साथ ही आगामी परीक्षाओं के लिए भी सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के जन्मदिवस पर लखनपुर में विशेष पूजा-अर्चना,मंत्री राजेश अग्रवाल ने मरीजों को बाटे फल



—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 21 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के जन्मदिवस के अवसर पर आज पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने लखनपुर स्थित मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर मुख्यमंत्री के स्वस्थ, दीर्घ और यशस्वी जीवन की कामना की। इस अवसर पर प्रदेश की सुख-समृद्धि, विकास और जनकल्याण के लिए विशेष प्रार्थना की गई। मंत्री अग्रवाल ने पूजा-अर्चना के उपरांत लखनपुर स्थित स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर भर्ती मरीजों से मुलाकात की। उन्होंने मरीजों का कुशलक्षेम जाना, उनका हालचाल पूछा तथा उन्हें फल वितरित कर शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इस दौरान स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों एवं स्टाफ से भी चर्चा कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी का जीवन सादगी, सेवा और समर्पण का प्रतीक है। उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास और सुशासन की नई ऊँचाइयों को छू रहा है। हम सभी उनके जन्मदिवस पर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु प्रदान करें, ताकि वे प्रदेश की जनता की सेवा इसी समर्पण भाव से करते रहें। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश में पर्यटन, संस्कृति, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों ने भी सहभागिता निभाई तथा प्रदेश की निरंतर उन्नति और समृद्धि की कामना की।

कांग्रेस का आरोप: फार्म-7 के जरिए मतदाताओं के नाम कटवाने का प्रयास विफल

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 21 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण के बाद जारी अंतिम मतदाता सूची को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजीव भवन में आयोजित प्रेसवार्ता में जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कहा कि फार्म-7 के माध्यम से वैध मतदाताओं के नाम कटवाने का भाजपा का दुर्भावनापूर्ण प्रयास विफल हो गया है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि फार्म-7 के जरिए जानबूझकर वैध मतदाताओं के नाम कटवाने का प्रयास करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 212 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए।



हजारों नाम कटवाने का प्रयास:

कांग्रेस : प्रेसवार्ता में बताया गया कि गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने संगठित रूप से जिले के हजारों मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फार्म-7 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किए थे। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक और निगम में नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद के नेतृत्व में प्रशासन

से मुलाकात कर इस प्रयास के खिलाफ साक्ष्य सहित शिकायत दर्ज कराई थी। जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) की प्रक्रिया का उपयोग कर भाजपा अपने अनुकूल मतदाता सूची तैयार करने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने कहा कि ऐसे मतदान केंद्रों को चिन्हित किया गया, जहां कांग्रेस को बहुत मिलती रही है, और वहां

कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम हटाने का प्रयास किया गया। हालांकि कांग्रेस के सक्रिय बीएलए, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ताओं की सज्जता के चलते यह प्रयास सफल नहीं हो पाया।

श्री पाठक ने इस सक्रियता का श्रेय पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव को दिया, जिन्होंने छह बार समीक्षा बैठक कर कार्यकर्ताओं को तैयार किया।

72 हजार मतदाताओं की कमी : कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने बताया कि जनवरी 2025 की तुलना में वर्तमान मतदाता सूची में जिलेभर में लगभग 72 हजार मतदाताओं की कमी दर्ज की गई है। निर्वाचन विभाग के अनुभार स्थानांतरण, मरुतु या अनुपस्थिति के कारण यह गिरावट आई है। कांग्रेस ने मतदान केंद्रों के जांच शुरू करने की बात कही है।

कानूनी कार्रवाई की चेतावनी : प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष जे.पी. श्रीवास्तव ने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फार्म-7 दिए गए थे, उनका नाम सूची में यथावत रहना ही इस बात का प्रमाण है कि आवेदन दुर्भावनापूर्ण थे। उन्होंने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि अन्यथा पार्टी का लीगल सेल न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के अन्य हिस्सों में भी भाजपा इस प्रकार की प्रवृत्ति अपनाकर मतदाता सूचियों में गड़बड़ी कर चुनाव जीतती रही है, लेकिन सरगुजा में उनका प्रयास उजागर हो गया है। प्रेसवार्ता के दौरान मो. इस्लाम, इफान सिद्दकी, इंद्रजीत सिंह धंजल, दुर्गेश गुप्ता, अतुल तिवारी, जमील खान, रशीद अहमद, नरेंद्र विश्वकर्मा, आशीष जायसवाल सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

युवा मोर्चा मण्डल जरही के मंत्री बने गौरव मिश्रा

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 21 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।



भारतीय जनता युवा मोर्चा जरही में संगठन विस्तार के तहत नवनियुक्त पदाधिकारियों की घोषणा की गयी है। इस क्रम में सक्रिय युवा सामाजिक कार्यकर्ता और युवा नेता गौरव मिश्रा को मण्डल जरही के मंत्री पद दी गयी है। भाजपा मण्डल अध्यक्ष श्री मुकेश सिंह एवं भाजयुमो मण्डल अध्यक्ष प्रतिक जायसवाल ने नव नियुक्त मंत्री को बधाई देते हुए विश्वास जताया है कि वे संगठन के नीतियों और विचारधारा को जनता के बीच पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। गौरव मिश्रा ने अपनी न्युक्ति पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे संगठन के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण भाव से कार्य करेंगे।

सोनहत-देवगढ़ वन परिक्षेत्र में लकड़ी तस्करी का जाल

बेशकीमती वन संपदा पर संगठित हमला



झारखंड नंबर टुक की जल्दी : एक बड़ी कार्रवाई या सिर्फ एक कड़ी ?

तीन दिन पूर्व वन विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर अवैध लकड़ी से लदे एक झारखंड नंबर के ट्रक को जब्त किया, प्राप्त जानकारी के अनुसार, सोनहत के बेलिया जंगल में विशेष टीम ने नाकेबंदी की, जांच के दौरान ट्रक से भारी मात्रा में कीमती लकड़ी बरामद हुई, चालक मौके से फरार हो गया, परमिट और टीपी (ट्रांजिट पास) की जांच में पाया गया कि प्राइवेट भूमि के नाम पर सिंगल परमिट बनवाकर उसकी आड़ में लकड़ी का परिवहन किया जा रहा था, बरामद लकड़ी की अनुमानित बाजार कीमत 7 से 8 लाख रुपये बताई जा रही है। ट्रक और लकड़ी को जब्त कर विभागीय डिपो में खड़ा कराया गया है, हालांकि स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि एक ट्रक पकड़ा गया है, तो यह संकेत है कि तस्करी का नेटवर्क व्यापक हो सकता है।

—राजन पाण्डेय—
बैकुंठपुर, 21 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

सोनहत विकासखंड के अंतर्गत आने वाले सोनहत एवं देवगढ़ वन परिक्षेत्र में इन दिनों वन संपदा की सुरक्षा पर गंभीर

प्रश्नचिह्न खड़े हो रहे हैं, सूत्रों के अनुसार क्षेत्र में बेशकीमती इमारती लकड़ियों की अवैध कटाई और तस्करी का संगठित नेटवर्क सक्रिय है, जो जंगलों के अंदरूनी हिस्सों से लकड़ी काटकर रात के अंधेरे में बाहर

पार कर रहा है, वन संपदा की इस निरंतर हो रही क्षति से शासन को लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है, वहीं पर्यावरणीय संतुलन पर भी खतरा मंडरा रहा है।



दुर्गम इलाकों में चल रहा खेल

जानकारी के मुताबिक देवगढ़ परिक्षेत्र के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में गश्त की कमी का लाभ उठाकर तस्करी सक्रिय है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जंगल के भीतर बड़े पैमाने पर इमारती लकड़ियों की कटाई हो रही है, लेकिन कार्रवाई छिटपुट ही नजर आती है, कुछ सूत्रों का यह भी दावा है कि इस अवैध कारोबार में अंदरखाने एक संगठित तंत्र काम कर रहा है, जो परमिट व्यवस्था की खामियों और सीमित निगरानी का फायदा उठा रहा है, हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।

पर्यावरण और वन्यजीवों पर खतरा

लगातार हो रही कटाई और छल निकासी से जंगलों का घनत्व कम हो सकता है, मिट्टी कटाव की समस्या बढ़ सकती है, वर्षा चक्र और जल स्रोत प्रभावित हो सकते हैं, वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट होने पर वे रिहायशी क्षेत्रों की ओर रुख कर सकते हैं, ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में स्थिति गंभीर रूप ले सकती है।

विभागीय कार्रवाई पर उठते सवाल-

हालिया जल्दी कार्रवाई के बावजूद यह सवाल बना हुआ है कि क्या तस्करी की जड़ तक पहुंचने के प्रयास हो रहे हैं? स्थानीय लोगों की मांग है कि नियमित रात्रिकालीन गश्त बढ़ाई जाए, संयुक्त अभियान चलाकर बड़े नेटवर्क का खुलासा किया जाए, परमिट और ट्रांजिट पास व्यवस्था की सख्त जांच हो, दोषी पाए जाने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

लोथ छाल की तस्करी: वर्षों से जारी काला कारोबार

इमारती लकड़ियों के अलावा लोथ पेड़ की छाल की तस्करी भी वर्षों से जारी बताई जा रही है, सोनहत से लेकर रामगढ़-छतरंग क्षेत्र तक लोथ की छाल बड़े पैमाने पर निकाली जा रही है, ग्रामीणों के अनुसार, तस्कर गांवों में संपर्क बनाकर छाल निकलवाते हैं, स्थानीय स्तर पर कम कीमत पर खरीद कर इसे सूरजपुर और अम्बिकापुर जैसे बाजारों में 80-100 रुपये प्रति किलो तक बेचा जाता है, इस छाल का उपयोग अगरबत्ती, साबुन और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं के निर्माण में होता है, वन विशेषज्ञों का कहना है कि यदि पेड़ से अत्यधिक मात्रा में छाल निकाली जाती है, तो पेड़ सूखने लगता है और अंततः नष्ट हो जाता है। इससे जैव विविधता पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है।

प्रशासन से अपेक्षा

वन संपदा केवल राजस्व का स्रोत नहीं, बल्कि पर्यावरण, जल संरक्षण और जैव विविधता का आधार है, सोनहत-देवगढ़ क्षेत्र की वर्तमान स्थिति यह संकेत दे रही है कि निगरानी तंत्र को और सशक्त बनाने की आवश्यकता है, अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि वन विभाग और जिला प्रशासन इस मामले में कितनी व्यापक और निर्णायक कार्रवाई करते हैं, ताकि जंगलों की हरियाली और प्राकृतिक धरोहर को सुरक्षित रखा जा सके।

जल संसाधन विभाग कार्यालय चपरासी के भरोसे संचालित, व्यवस्था पर गंभीर सवाल



—संवाददाता—
खड़गवां (एमसीबी), 21 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

एमसीबी जिले के खड़गवां विकासखंड में स्थित जल संसाधन विभाग का स्थानीय कार्यालय इन दिनों बदहल कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा में है, आरोप है कि विभागीय अधिकारी और जिम्मेदार कर्मचारी नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित नहीं रहते, जिसके कारण पूरा कार्यालय व्यावहारिक रूप से एक चपरासी के भरोसे संचालित हो रहा है।

ग्रामीणों और किसानों का कहना है कि सिंचाई, नहर मरम्मत, जल वितरण, मोटर पंप स्वीकृति, मरम्मत प्रस्ताव और लंबित भुगतान जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए जब वे कार्यालय पहुंचते हैं, तो उन्हें संबंधित अधिकारी या तकनीकी कर्मचारी नहीं मिलते, अक्सर आवेदन और शिकायत पत्र चपरासी को ही सौंपने पड़ते हैं, ग्रामीणों का आरोप है कि कई मामलों में शिकायतें दर्ज तो हो जाती हैं, पर उनकी प्रगति की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती, फाइलें कार्यालय में लंबित पड़ी रहती हैं और उनका निस्तारण अनिश्चित काल तक टलता रहता है।

रबी सीजन में पानी संकट

रबी फसल के समय सिंचाई की निर्बाध व्यवस्था अत्यंत आवश्यक होती है। क्षेत्र के किसानों का कहना है कि कई नहरों की समय पर सफाई और मरम्मत नहीं हो पाई है, कुछ जगहों पर पानी का प्रवाह बाधित है, जल वितरण का शेड्यूल स्पष्ट

नहीं है, किसानों का आरोप है कि यदि समय पर निरीक्षण और मॉनिटरिंग होती, तो समस्याएं बढ़ती नहीं। पानी की अनियमित आपूर्ति से गेहूं, चना और अन्य रबी फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।

तकनीकी निगरानी का अभाव

जल संसाधन विभाग का कार्य केवल कार्यालयी प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय निरीक्षण, नहरों की स्थिति का आकलन, पानी के प्रवाह की निगरानी और शिकायतों का स्थल पर समाधान भी इसकी जिम्मेदारी है, ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में क्षेत्र में विभागीय निरीक्षण कम हो देखने को मिले हैं, इससे यह आशंका बढ़ रही है कि तकनीकी स्तर पर भी निगरानी कमजोर हो गई है।

स्टाफ की कमी या प्रशासनिक लापरवाही ?

सूत्रों के अनुसार कार्यालय में पदस्थ कुछ कर्मचारी लंबे समय से नियमित उपस्थिति दर्ज नहीं करा रहे हैं, वहीं विभागीय सूत्रों का कहना है कि स्टॉफ की कमी, अतिरिक्त प्रभार और अन्य प्रशासनिक दायित्वों के कारण स्थिति उत्पन्न हुई है, हालांकि नागरिकों का सवाल है कि यदि स्टॉफ की कमी है तो, वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? उच्चाधिकारियों को स्थिति की जानकारी क्यों नहीं दी गई? जनहित के कार्यों को प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई?

पारदर्शिता पर उठे सवाल-

कार्यालय की कार्यप्रणाली को लेकर पारदर्शिता का अभाव भी चर्चा का विषय है, ग्रामीणों का कहना है कि आवेदन की स्थिति, कार्यों की प्रगति और बजट उपयोग की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, यदि शिकायतों का समयबद्ध निराकरण और कार्यों की नियमित समीक्षा होती, तो स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती।

प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग...

स्थानीय नागरिकों, किसान संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि, कार्यालय की नियमित उपस्थिति की जांच कराई जाए, लंबित फाइलों और कार्यों की समीक्षा की जाए, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए, सिंचाई और जल प्रबंधन कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए, जनहित से जुड़े इस महत्वपूर्ण विभाग की वर्तमान स्थिति प्रशासनिक तंत्र पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े करती है। यदि समय रहते सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो इसका सीधा असर किसानों की आजीविका और क्षेत्रीय कृषि उत्पादन पर पड़ सकता है, अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और क्या जल संसाधन विभाग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो पाती है या नहीं।

कोरिया का 'जल-क्रांति' मॉडल अब बनेगा राष्ट्रीय नीति का आधार

'आवा पानी झोंकी अभियान' से निकला 5 प्रतिशत मॉडल पूरे देश में लागू करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल

मॉडल के प्रमुख बिंदु

प्रत्येक किसान अपनी कुल कृषि भूमि का 5 प्रतिशत हिस्सा जल संरचना हेतु चिन्हित करता है।

इस हिस्से में सीढ़ीनुमा सोखता गड्ढा या संरचना बनाई जाती है।

वर्षा के दौरान खेत में गिरने वाला पानी इन संरचनाओं में एकत्रित होकर धीरे-धीरे जमीन में समा जाता है।

इससे भूजल पुनर्भरण होता है और आसपास के हैंडपंप, कुएं तथा बोरेवेल में जलस्तर सुधरता है।

खेत में नमी की अवधि बढ़ती है, जिससे फसल उत्पादन में सुधार होता है, यह मॉडल कम लागत वाला है और स्थानीय संसाधनों से तैयार किया जा सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है।

राष्ट्रीय स्तर पर क्यों महत्वपूर्ण ?

भारत के कई राज्य गिरते भूजल स्तर और अनियमित वर्षा से जूझ रहे हैं, ऐसे में कोरिया का 5 प्रतिशत मॉडल एक व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करता है, यदि इसे राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बनाया जाता है, तो छोटे किसानों को कम लागत में जल सुरक्षा मिलेगी, जल संरक्षण को जन-आंदोलन का रूप दिया जा सकेगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थायित्व मिलेगा, जल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ठोस कदम बढ़ेगा, केंद्रीय स्तर पर इस मॉडल को अन्य राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप अनुकूलित करने पर विचार किया जा रहा है।

कोरिया बना 'जल-नायक'

यह उपलब्धि केवल एक प्रशासनिक घोषणा नहीं, बल्कि कोरिया जिले के ग्रामीणों, किसानों और प्रशासन की संयुक्त मेहनत की कहानी है, एक छोटे से जिले का नवाचार अब राष्ट्रीय नीति निर्माण में स्थान पा रहा है, कोरिया ने यह साबित कर दिया है कि विकास केवल बजट और संसाधनों से नहीं, बल्कि दूरदर्शिता, सामुदायिक सहभागिता और स्थानीय समाधान से भी संभव है, आज 'आवा पानी झोंकी अभियान' एक जिले की पहल से आगे बढ़कर देश के लिए जल-सुरक्षा की प्रेरक मिसाल बन चुका है।



—राजन पाण्डेय—

कोरिया, 21 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्र कोरिया जिला से शुरू हुई जल संरक्षण

की एक स्थानीय पहल अब राष्ट्रीय पहचान हासिल कर चुकी है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की मौजूदगी में आयोजित उच्च

स्तरीय बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि कोरिया जिले का '5 प्रतिशत जल संरक्षण मॉडल' देशभर में लागू

करने की दिशा में नीति-स्तर पर पहल की जाएगी, यह निर्णय केवल प्रशासनिक उपलब्धि नहीं, बल्कि स्थानीय नवाचार को राष्ट्रीय मंच पर मिली स्वीकृति का प्रतीक है।

क्या है '5 प्रतिशत मॉडल'? (एक नजर में)	
विशेषता	विवरण
अभियान का नाम	आवा पानी झोंकी अभियान
संरचना	खेत/बाड़ी के 5% हिस्से पर सीढ़ीनुमा सोखता गड्ढा
मुख्य लाभ	भूजल पुनर्भरण, मिट्टी की नमी में वृद्धि, शुष्क लागत में सिंचाई सुरक्षा
प्रभाव	कृषि उत्पादकता में 20-30% तक की वृद्धि की संभावना

'आवा पानी झोंकी अभियान' क्या है ?

कोरिया जिले में प्रारंभ किया गया 'आवा पानी झोंकी अभियान' एक जनभागीदारी आधारित जल संरक्षण कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य वर्षा जल को अधिकतम मात्रा में भूमि के भीतर समाहित कर भूजल स्तर को स्थिर एवं समृद्ध करना है, इस अभियान के अंतर्गत किसानों और ग्रामीणों को यह समझाया गया कि जल संकट का समाधान बड़े बांधों या भारी परियोजनाओं में ही नहीं, बल्कि छोटे और व्यवहारिक उपायों में भी छिपा है।

क्या है '5 प्रतिशत मॉडल' ?

इस मॉडल की मूल अवधारणा सरल है लेकिन परिणाम प्रभावशाली हैं।

प्रशासनिक नेतृत्व और मैदानी क्रियान्वयन

इस अभियान को जन-आंदोलन का रूप देने में जिला कलेक्टर चंदन त्रिपाठी की भूमिका महत्वपूर्ण रही। प्रशासन ने गांव-गांव शिबिर लगाकर किसानों को प्रशिक्षित किया, बैकुंठपुर और सोनहत क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाए गए, तकनीकी अमले ने खेतों का निरीक्षण कर संरचना की रूपरेखा तैयार की, किसानों को स्वैच्छिक श्रमदान के लिए प्रेरित किया गया, जिला पंचायत सीईओ डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने इसे सामूहिक इच्छाशक्ति का परिणाम बताया, उनके अनुसार यह मॉडल दर्शाता है कि यदि स्थानीय स्तर पर ठोस नेतृत्व और जनसहभागिता हो, तो सीमित संसाधनों में भी बड़ी उपलब्धि संभव है।

परिणाम: धरातल पर दिखता असर

अभियान के प्रारंभिक परिणाम उत्साहजनक बताए जा रहे हैं, वर्षा जल का अधिकतम भू-गर्भ में समावेशन, खेतों में नमी की अवधि में वृद्धि, रबी फसलों के उत्पादन में सुधार, सिंचाई लागत में कमी, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में स्थिरता, कुछ क्षेत्रों में किसानों ने बताया कि पिछले वर्षों की तुलना में जलस्तर में सकारात्मक बदलाव देखा गया है।

बजट सत्र में पेश होगा धर्मांतरण विरोधी कानून के लिए विधेयक

रायपुर,21 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में सरकार धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने के लिए छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक पेश करेगी। इसके साथ ही दो अन्य महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन में प्रस्तुत किए जाएंगे। सत्र के लिए अब तक 28 सी से अधिक प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजट



सत्र की प्रस्तावित कार्यवाही की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सत्र के पहले दिन 23 फरवरी को दिवंगत पूर्व सदस्य दीनदयाल सिंह पोतों की श्रद्धांजलि दी जाएगी। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी, जबकि राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर 25 फरवरी को चर्चा होगी। स्पीकर ने बताया कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी 24 फरवरी को दोपहर साढ़े 12 बजे बजट पेश करेंगे। 26 और 27 फरवरी को आय-व्यय पर सामान्य चर्चा होगी। इसके बाद 9 से 17 मार्च तक विभागवार अनुदान मांगों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। डॉ. सिंह ने बताया कि प्रशासकीय विधि-विषयक कार्यों के तहत तीन विधेयकों की सूचना प्राप्त हुई है। इनमें छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक, छत्तीसगढ़ लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन विधेयक तथा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित एक अन्य विधेयक शामिल है।

तेज रफतार कार डिवाइडर से टकराकर बिजली पोल से भिड़ी,दो सगे भाई समेत तीन की मौत

रायपुर,21 फरवरी 2026। जिले के पारागांव के पास बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो सगे भाइयों समेत तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना आरंग थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक महासमुंद से आरंग की ओर आ रही सफेद रंग की टाटा विस्टा क्रमांक सीजी 04 एचडी 2156 नदी मोड़ के पास अनियंत्रित हो गई। तेज रफतार कार पहले डिवाइडर से टकराई और फिर बिजली के पोल से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार तीन युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान छुरा थाना क्षेत्र के सरगांव निवासी सगे भाई हर्ष कुमार देवांगन (21) और राहुल देवांगन (20) के रूप में हुई है। दोनों हाल ही में आरंग स्थित परमेश्वरी फोटो स्टूडियो में कार्यरत थे। तीसरे मृतक की पहचान थानू सतनामी (22), निवासी ग्राम ओड्डका, थाना आरंग के रूप में हुई है। हादसे में घायल मिथलेखा धीवर (23), निवासी ब्लॉक आरंग को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि चारों युवक महासमुंद अपने एक रिश्तेदार को छोड़ने गए थे और लौटते समय यह हादसा हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफतार के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका, जिससे कार रेलिंग तोड़ते हुए डिवाइडर से टकरा गई। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। राहगीरों की सूचना पर पुलिस और एंबुलेंस टीम पहुंची। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।



छत्तीसगढ़ के अफसरों के लिए बड़ी खुशखबरी...सरकार ने बदला नियम अब 50% पदों पर होगी सीधी पदोन्नति

रायपुर,21 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए प्रमोशन का कोटा 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब राज्य सेवा के हर 100 पदों में से 50 पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे, जिससे लंबे समय से कतार में खड़े अनुभवी अफसरों के लिए तरक्की के नए रास्ते खुल गए हैं। दरअसल इस फैसले से तहसीलदार,नायब तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा। फील्ड स्तर पर अनुभवी अधिकारियों की संख्या बढ़ने से राजस्व मामलों, कानून-व्यवस्था और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी,जिसका सीधा लाभ छत्तीसगढ़ की आम जनता को मिलेगा। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ लंबे समय से पदोन्नति के कोटों को 50-50 करने की मांग कर रहा था। सरकार के इस निर्णय से प्रमोशन स्टैगनेशन (पदोन्नति में ठहराव) खत्म होगा। अब अनुविभाग और जिला स्तर पर काम करने वाले अफसरों को समय पर उच्च पदों जैसे उपा सचिव स्तर तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। जानकारों का मानना है कि इस बदलाव से प्रशासनिक कसावट आएगी क्योंकि मैदानी स्तर का अनुभव रखने वाले अफसर अब नीति निर्धारण में अधिक संख्या में शामिल होंगे।



छत्तीसगढ़ में अब 1 करोड़ 87 लाख मतदाता

एसआईआर के बाद बढ़े 2.34 लाख वोटर्स,रायपुर में 30 हजार वोटर कम हुए

रायपुर,21 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ में मतदाताओं की फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (एसआईआर) के तहत नाम जोड़ने, हटाने के लिए बुलाए गए दावे-आपत्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश में वोटरों की संख्या 1 करोड़ 87 लाख 30 हजार 914 हो गई है। ड्राफ्ट के बाद 2 लाख 34 हजार 994 वोटरों की संख्या बढ़ी है। वहीं, 1 लाख 8 हजार 807 वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। इनमें ऐसे मतदाता शामिल हैं, जिनमें किसी की मौत हो चुकी है, जो कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं। सबसे ज्यादा रायपुर में 30 हजार वोटरों के नाम कटे हैं, कोरबा में 15 हजार और दुर्ग में 7 हजार वोटरों के नाम कटे हैं।

छत्तीसगढ़ में 27 हजार से ज्यादा वीएलओ ने किया सर्वे

एसआईआर के पूरे अभियान में 27,196 बूथ लेवल अधिकारियों ने घर-घर जाकर गणना फॉर्म वितरित किए। मृत स्थायी रूप से स्थानांतरित और डुप्लीकेट नामों की पहचान कर सूची को अपडेट किया गया। इश दौरान करीब 1.84



दावे-आपत्तियों का तय समय में निराकरण

23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 के बीच नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए दावे-आपत्तियां ली गईं। सभी आवेदनों का निराकरण 14 फरवरी 2026 तक कर लिया गया। जिन मतदाताओं के फॉर्म वापस नहीं मिले, उनकी विधानसभा-वार सूची आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की गई।

करोड़ मतदाताओं के गणना फॉर्म का डिजिटलीकरण किया गया। राजनीतिक दलों को मुफ्त में उपलब्ध कराई गई सूची : हर जिले में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अंतिम

मतदाता सूची की दो प्रतियां (एक फोटोयुक्त प्रिंटेड और एक बिना फोटो सॉफ्ट कॉपी) निशुल्क उपलब्ध कराई गई हैं। एसआईआर के दौरान प्राप्त नवीनतम फोटो भी सूची में अपडेट किए गए हैं।

बिलासपुर में फूड इंस्पेक्टर 90000 रिश्तव लेते गिरफ्तार

राशन दुकान के आवंटन के लिए मांगे 1 लाख,एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा

बिलासपुर,21 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर एसीबी की टीम ने मस्ती के फूड इंस्पेक्टर को 90,000 रुपए रिश्तव लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। फूड इंस्पेक्टर ने स्व सहायता समूह को सरकारी उचित मूल्य की दुकान आवंटन करवाने के एवज में 1 लाख रुपए रिश्तव मांगा था। इसकी शिकायत एसीबी बिलासपुर से की थी। एसीबी की टीम ने शनिवार को फूड इंस्पेक्टर को उसके घर से रिश्तव लेते हुए गिरफ्तार किया। एसीबी ने आरोपी फूड इंस्पेक्टर से 90,000 रुपए की रकम बरामद कर ली है।



सरकारी उचित मूल्य के लिए दिया था आवेदन

डीएसपी एसीबी बिलासपुर अजितेश सिंह ने बताया कि ग्राम विद्याडीह के निवासी महेंद्र पटेल ने 3 फरवरी 2026 को एसीबी बिलासपुर से शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया कि गांव में सरकारी उचित मूल्य की दुकान वर्तमान में पंचायत चला रही है। इसे स्व सहायता समूह विद्याडीह को देने के लिए समूह के अध्यक्ष ने

करीब तीन महीने पहले एसडीएम कार्यालय मस्ती में आवेदन दिया था।

फूड इंस्पेक्टर ने मांगा 1 लाख रिश्तव : महेंद्र पटेल ने बताया कि फूड इंस्पेक्टर श्याम वस्त्रकार ने समूह के लिए जांच रिपोर्ट और दुकान का आवंटन आदेश जारी करवाने के बदले 1 लाख रुपए रिश्तव मांगी। महेंद्र पटेल ने रिश्तव देने से इनकार किया और एसीबी को सूचित किया ताकि फूड इंस्पेक्टर को रिश्तव लेते हुए पकड़ा जा सके।

छत्तीसगढ़ में 86 साल की बुजुर्ग महिला से दरिदगी...25 साल के युवक ने किया दुष्कर्म,गंभीर हालत में चल रहा इलाज

धमतरी,21 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक 86 साल की महिला के साथ 25 साल के युवक ने दुष्कर्म किया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। दुष्कर्म का शिकार हुई बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर बनी हुई है, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिले की कुरुद थाना पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, दिल दहला देने वाला यह मामला कुरुद थाना इलाके का है, जहां 18 फरवरी 2026 को 25 साल के एक युवक ने 86 साल की बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म



किया। घटना के समय बुजुर्ग महिला घर में अपने दो छोटे नातियों के साथ थी। आरोपी ने बच्चों को चॉकलेट देकर बहलाने की कोशिश की, इस दौरान वे वहां से भाग गए। इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म किया।

युवा कांग्रेस ने भाजपा कार्यालय घेरने की कोशिश की...रास्ते में पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झूमाझटकी,अस्थायी गिरफ्तारी भी हुई

रायपुर,21 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस आज भाजपा कार्यालय का घेराव करने निकली थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें कार्यालय पहुंचने के पहले ही रोक दिया। युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा की अगुवाई में हुए प्रदर्शन के दौरान रैली रायपुर के राजीव गांधी चौक से शुरू होकर एकाम परिसर की तरफ बढ़ी। सैकड़ों की संख्या में जुटे कार्यकर्ता 'PM is Compromised' के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। हालांकि, भाजपा कार्यालय से पहले ही पुलिस प्रशासन ने भारी बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक दिया। जैसे जैसे कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने की कोशिश की, पुलिस और



प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झूमाझटकी शुरू हो गई। कुछ देर तक मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति बनी रही। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर बाद में अस्थायी रूप से छोड़ दिया।

युवा कांग्रेस ने कहा- सरकार के दबाव में पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक रोका : आंदोलन के दौरान युवा कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने केंद्र और राज्य सरकार के दबाव में

कार्रवाई की। उनका कहना था कि वे शांतिपूर्ण तरीके से भाजपा नेतृत्व तक अपने सवाल पहुंचाने जा रहे थे, लेकिन उन्हें बलपूर्वक रोका गया।

युवा कांग्रेस ने भाजपा नेतृत्व पर उठाए सवाल : युवा कांग्रेस का कहना है कि 'PM is Compromised' सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि देश के बेरोजगार युवाओं की भावनाओं की अभिव्यक्ति है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या नेता प्रतिपक्ष को गोली मारने जैसी बयानबाजी से देश की छवि खराब नहीं होती? क्या विदेशी तकनीक को अपना नवाचार बनाने से देश की साख पर असर नहीं पड़ता?

डिप्टी सीएम साव का ऐलान...छत्तीसगढ़ी बनेगी राजभाषा पं. श्यामलाल चतुर्वेदी की जन्म शताब्दी पर किया वादा

बिलासपुर,21 फरवरी 2026। डिप्टी सीएम अरुण साव ने घोषणा की है कि पद्मश्री पं. श्यामलाल चतुर्वेदी के सपने को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। यह बात उन्होंने शुक्रवार को बिलासपुर के लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में पं. चतुर्वेदी की जन्म शताब्दी समारोह में कही। समारोह की अध्यक्षता दिल्ली और रायपुर के वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने ने की। इस अवसर पर पं. चतुर्वेदी पर केंद्रित एक स्मृति ग्रंथ का विमोचन किया गया, जिसका संपादन वरिष्ठ पत्रकार रूद्र अवस्थी ने किया है। साथ ही, पं. चतुर्वेदी की छत्तीसगढ़ी पुस्तिका 'भोलवा भोलाराम बनिस' और डॉ. सुषमा शर्मा द्वारा प्रकाशित इसके हिंदी अनुवाद का भी विमोचन हुआ। कार्यक्रम में महापौर पूजा विधानी, नगर विधायक अमर अग्रवाल,लिह्ला विधायक धरमलाल कौशिक, कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव,बेलतरा विधायक सुरांत शुक्ला सहित कई साहित्यकार और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि 2 अप्रैल 2018 को जब पं. चतुर्वेदी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो यह पूरे छत्तीसगढ़ की संस्कृति और



सबने माना पं चतुर्वेदी छत्तीसगढ़ का चेहरा थे...

कार्यक्रम में शामिल विद्वान वक्ता,पत्रकार,बुद्धिजीवियों ने माना कि छत्तीसगढ़ की भाषा,संस्कृति और परंपरा की बात करें तो पं चतुर्वेदी छत्तीसगढ़ के चेहरे के रूप में उभर कर सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि पं चतुर्वेदी सही मायने में छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश की धरोहर माने जा सकते हैं।

छत्तीसगढ़ी को गुरतुर गोट के रूप में स्थापित किया: पाठक

छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. विनय पाठक ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मौलिक सुजन को 'गुरतुर गोट' के रूप में स्थापित करना उनकी विशिष्ट पहचान रही है। उनकी भाषा लोकलका और लोकजीवन की आत्मा से निर्मित थी। उन्होंने कहा कि पं चतुर्वेदी पर उनके निर्देशन में चार खंड पीएचडी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि पं चतुर्वेदी की 'बेटी के बिदा' कविता बेहद चर्चित रही। उनके लेखन, व्यक्तित्व में लोक बसता था।

सभ्यता का सम्मान था। उन्होंने पं. चतुर्वेदी को बहुमुखी प्रतिभा का धनी बताया, जो एक कवि, साहित्यकार और पत्रकार होने के साथ-साथ बेबाक वक्ता भी थे। साव ने आगे कहा कि पं. चतुर्वेदी 100 प्रतिशत छत्तीसगढ़ी संस्कारों से ओत-प्रोत थे। उनकी निरंतर साहित्य साधना और जीवन शैली हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की माटी, भाषा और लोक संस्कारों को आगे बढ़ाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी रहे, और छत्तीसगढ़ी भाषा के संवर्धन में उनका योगदान अविस्मरणीय है। डिप्टी सीएम ने दोहराया कि पं. चतुर्वेदी की स्मृति को अक्षुण्ण रखने और छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार हर संभव प्रयास करने को प्रतिबद्ध है।

छत्तीसगढ़ की प्रतिमूर्ति थे: उपासने

वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने ने कहा कि वे छत्तीसगढ़ की प्रतिमूर्ति थे और प्रदेश के विविध आयामों को समेटने वाले अमर पुरुष थे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ी में कहवत है कि घर के जोगी जोगड़ा...वाकई में पं चतुर्वेदी सिद्ध पुरुष थे,मैंने दिल्ली में खुद देखा है कि कैसे उनका नाम सुनते ही चमत्कार हो जाता।

रायपुर,21 फरवरी 2026। राज्य विद्युत नियामक आयोग की जनसुनवाई हुई। इस दौरान घरेलू उपभोक्ताओं को नियमानुसार सुविधा देने का मुद्दा उठा। पूर्व प्रोफेसर घनाराम साहू ने स्मार्ट मीटर की टेस्ट रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराए जाने की शिकायत के साथ कई सुझाव प्रस्तुत किए। पूर्व प्रोफेसर साहू ने मांग की कि स्मार्ट मीटर लगाने से पहले टेस्ट रिपोर्ट दी जाए तथा मीटर रीडिंग में संदेह होने पर प्रमाणित चेक मीटर लगाया जाए। साथ ही उपभोक्ताओं को तकनीकी जानकारी और वार्षिक लेखा विवरण उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने का भी सुझाव उन्होंने दिया।

पूर्व आईएसएस पांडेय ने पेश की याचिका

निजी भूमि पर विद्युत उपकरण स्थापना से पूर्व मुआवजा, शिकायत के लिए अतिरिक्त फोन नंबर और विभागीय नियमों का हिंदी अनुवाद उपलब्ध कराने की भी मांग की गई। पूर्व आईएसएस अनुराग पांडेय ने किसान नेता भूपेन्द्र शर्मा के साथ कृषि क्षेत्र हेतु विद्युत दरों एवं संबंधित विषयों पर एक याचिका प्रस्तुत की। याचिका में किसानों और आम उपभोक्ताओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए। इस याचिका में मांग की गई है कि जनसुनवाई हेतु प्रस्तुत सभी प्रस्ताव हिंदी में भी उपलब्ध कराए जाएं, ताकि आम उपभोक्ता और किसान प्रस्तावों को समझकर अपने सुझाव दे सकें। ग्रामीण एवं कृषि विद्युत आधारभूत संरचना के विकास के लिए विगत 50 वर्षों में सरकारों द्वारा दिए गए



अनुदान को केवल कृषि क्षेत्र में ही समायोजित करने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ऐसा करने से कृषि क्षेत्र की फिक्स्ड कॉस्ट शुल्क की जा सकेगी। कृषि उपभोक्ताओं को दिन के समय सरती बिजली उपलब्ध कराने के लिए 'Schedule and Discount' की सुविधा लागू करने की भी मांग की गई है। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि पिछले वर्षों में कृषि क्षेत्र की विद्युत दरों में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि उद्योग और वाणिज्यिक क्षेत्र में यह वृद्धि मात्र 6 प्रतिशत रही है। इसे संतुलित करने की आवश्यकता बताई गई है। इसके अलावा 5 हॉसपॉवर तक के पंपों को दी जा रही छूट को सभी पंपों पर लागू करने का अनुरोध किया गया है। आयोग ने प्रस्तुत सुझावों पर विचार करने का आश्वासन दिया है।